THE DEPUTY CHAIRMAN: No; it is not correct. ...*(Interruptions)*...

देखिए, इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। आप इतने अनुभवी हैं, आप चीफ-मिनिस्टर रह चुके हैं। मेरी आदत किसी को बचाने की नहीं है।

श्री मोती लाल वोराः महोदया, बचाने का मतलब यह है कि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न यहां ... iNst kusflsu is elauts eahtamudsfy, rskj his els (**व्यवधान**)... As image

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not a correct expression.

...*(Interruptions)*...

डा० मुरली मनोहर जोशीः उपसभापति महोदया, मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि मैं आज तक किसी प्रश्न से या किसी बहस से न बचाना चाहता हूं और न मैंने कभी बचने की कोशिश की है।

श्री मोती लाल वोराः मैंने यही कहा कि मंत्री जी तैयार होकर आए हैं ...(**व्यवधान**)...

डा० मुरली मनोहर जोशीः हुआ यह है कि जब-जब बहस होती रही है, लोगों ने कहा है कि अब बहस बंद कीजिए, बहुत बहस हो चुकी है। यह रिकार्ड पर है। शिक्षा के प्रश्न पर जितनी बार बहस हुई है, मैं आपके सामने यहां खड़ा रहा हूं और सम्मानित सदस्यों ने और उपसभापति महोदया ने यह कहा है कि अब बहस बंद होनी चाहिए, मैंने यह कभी नहीं कहा। मैं आपके हर प्रश्न का समाधान करने के लिए तैयार हूं। आपके मस्तिष्क में जितनी प्रकार की लघु अथवा दीर्ध शंकाएं होंगी, मैं उनका सबका समाधान करुंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I wish you understood why I said that there should be a full-fledged discussion because various sections ...*(Interruptions)*... Just a minute, please. He cannot discuss a policy on a question; and, if we discuss the policy,- you will have a better chance to talk about it. Now; Meenaji.

Vocational relevance to Education

* 162. SHRIMOOLCHAND MEENA:†
DR. T. SUBBARAMIREDDY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government and industry feel that Indian education system does not equip students with skills and is not job oriented;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Moolchand Meena.

(b) if so, whether Government have made vocational education a focus area, and industry and corporate bodies have been roped in, as part of the effort to provide education with vocational relevance;

(c) whether this question was also discussed at the Conference of State Education Secretaries, held in August, 2002; and

(d) if so, to what extent States have agreed to implement the suggestions made in the Conference in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) Government has taken steps for Vocationalisation of Education at different levels for making it job oriented. A Scheme of Vocationalisation of Secondry Education is being implemented to provide job oriented education at school level. The University Grants Commission also has a programme, namely, Career Orientation Scheme under which it has extended financial assistance to 35 Universities and 1635 Colleges. Efforts have been made to seek the cooperation of Industries and other corporate houses through Chamber of Indian Industries (CII), etc. for making the education job oriented.

(c) and (d) Since School Education is primarily the responsibility of State Governments, various issues involved in the Vocationalisation of Secondary Education, including involvement of industries and corporate houses were discussed at the Education Secretaries Conference held in August 2002. The State Governments have by and large supported the scheme of Vocationalisation of Education and the idea of developing linkages of vocational programmes with the industry for its success.

श्री मूल चन्द मीणाः उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वे शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने में कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि देश के अंदर व्यावसायिक विद्यालयों और कालेजों की संख्या कितनी है, यह राज्य-वार बताएं। मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि सरकार द्वारा देश में आवश्यकता के अनुसार अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसका विवरण दें। मैं यह भी जाना चाहता हूं कि 2 अगस्त, 2002 को शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में जो सुझाव आए थे, जिन सुझावों को माना गया था, उनको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है और आप कब तक इन्हें लागू करेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः पहली बात तो यह है कि इस बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि आठवीं पंचवर्षिय योजना के बाद यह व्यावसायिक शिक्षा की योजना का कार्यक्रम राज्य

सरकारों को नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह योजना वहां क्रियान्वित नहीं की गई। इसलिए हमने इसको नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और अब दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में विस्तृत रुप से रुपरेखा बनाई गई। जहां तक राज्य-वार स्कूलों का सवाल है वह इस प्रकार से हैः

आन्ध्र प्रदेश में 668 और एंरोलमेंट केपेसिटी 94 हजार, अरुणाचल प्रदेश स्कूल संख्या-4 और एंरोलमेंट 200, आसाम स्कूल 225 और एंरोलमेंट 25500, बिहार 251 और एंरोलमेंट 37600, गोवा 43 नम्बर आफ सैक्शन 106 और एंरोलमेंट केपेसिटी 5300, आप कहें तो सारे राज्यों की संख्या मेरे पास है, मैं इसे पढ़ सकता हूं।

इसमें मुझे कहना है कि राजस्थान सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने की अभी भी स्वीकृति नहीं दी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां स्कूल संख्या 910 और केपेसिटी एक लाख सत्तरह हजार पांच सौ है।

श्री मूल चन्द मीणाः उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि सरकार के विचार में तकनीकी शिक्षा के मामले में बढ़ रही क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए देश के पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हेतु आपकी कोई प्रोत्साहन कार्य योजना है? इस योजना को पिछड़े क्षेत्रों की असमानता को दूर करने के लिए संस्था खोलने में जो मानदंड हैं इसमें छूट देने की आपकी कोई योजना है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः महोदया, यह प्रश्न व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है और यह जो प्रश्न कर रहे हैं यह तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। इसके लिए दोबारा नोटिस देना पड़ेगा।

श्री मूल चन्द मीणाः व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो क्षेत्रीय असमानता है और किसी राज्यों में ज्यादा है और किसी राज्यों में कम है, उसके बारे में भी बताएं

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। वह अपने यहां विस्तार करें। हमारी तरफ से जो शिक्षा का प्रारुप है वह उनको दे दिया गया है, उसके लिए जो आर्थिक प्रबंध हम करते हैं, वह दे दिया गया है। बाकी वह अपने राज्यों में करते हैं या नहीं करते हैं, अब राजस्थान सरकार व्यावसायिक शिक्षा अपने यहां करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करेंगे।

श्री मूल चन्द मीणाः महोदया, मैंने यह जानना चाहा था कि अगस्त, 2002 में शिक्षा सचिवों की बैठक में उनके क्या सुझाव थे?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He wants to know because the vocational education would improve the job possibilities.

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः उसके लिए भी मैंने कहा कि जब वोकेशनल एजुकेशन का कार्यक्रम पूरी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर समाप्त प्रायः था, लोग कर नहीं रहे थे, तो राज्य सरकारों ने उसको स्वीकार किया और वहां ट्रांसफर हुआ। लेकिन उन्होंने योजना चलाई ही नहीं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में हमने इस योजना को फिर से शुरु किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना का अभी यह पहला वर्ष है। इसका परिणाम व्यवसाय के ऊपर और रोजगार के ऊपर कोई संबंध ही स्थापित नहीं हुआ। योजना चले इसमें से पढ़े-लिखे लोग निकल कर आएं तब वह रोजगार पूरा करे तो ठीक है। हां, विश्वविद्यालयों की जो व्यावसायिक शिक्षा है वह भी अभी इसी प्रकार से शुरु की गई है। 1635 कॉलेजेज के अंदर, और जब 3-4 साल में बी॰एस॰सी॰ कर लेगा बी॰ए॰ कर लेगा उसके बाद उसका प्रभाव पड़ेगा रोजगार के ऊपर कि उसको रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इस शिक्षा का उद्देश्य यह है कि एम्पलोएबिल रोजगारक्षम व्यक्ति तैयार किए जाएं।

श्री मूल चन्द मीणाः अगस्त, 2002 में शिक्षा सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्या-क्या सुझाव आए थे जहां किसी राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को लागू नहीं किया गया है तो इस संबंध में बतला दें कि शिक्षा सचिवों के क्या-क्या सुझाव माने गए थे, क्या निर्णय लिए गए थे और उन निर्णयों को लागू किया गया या नहीं?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों की बैठक में लिए गए निर्णय राज्य सरकारों को ही इम्पलीमेंट करने थे। अगस्त 2002 में निर्णय लिए गए और अभी नवम्बर, 2002 चल रहा है।

श्री मूल चन्द मीणाः वह निर्णय बतला दें कि क्या लिए गए थे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः लम्बी लिस्ट है।

श्रीमती सरोज दुबेः वह बतला दें क्योंकि शिक्षा सचिवों ने कुछ तो कहा होगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः उपसभापति महोदया, इसकी इन्फोरमेशन मैं बाद में दे दूंगा।

उपसभापतिः आप सदन के पटल पर रख देना।

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः उपसभापति महोदया, मैं इसकी इन्फारमेशन सभा पटल पर रख दूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rama Shanker Kaushik. No, Dr. Subbarami Reddy. He is the second questioner. Dr. Reddy, you keep speaking; so I forget.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Madam, I would like to know from tlie hon. Minister whether the Government feels that the Indian education system today equips students with skills, job-oriented skills. Madam, I would like to

draw his kind aRention to the main concept and philosophy behind this system. As of today, the education system is 2 x 2 = 4. When one finishes one's graduation, one is not sure of getting a job. Let us evolve a new system. Let us change the system of education, as much as possible, so that a graduate can get a suitable job as a carpenter or as a fitter or as a technician or some such avocation. So, I am also happy that the Minister has said that Rajiv Gandhi's Education Policy is the best policy. It was evolved in 1986. Of course, the previous Government did not implement it. So, my first question is: To what extent the present Government has succeeded in implementing Education Policy promoted by late Shri Rajiv Gandhi? Madam^ part (b) of my question is: To what extent they have been successful in ushering in new era, so that the world could know that the Indian education system, under the great leadership of Dr. Murh Manohar Joshi has undergone a great change! How far can we say that the old and outdated system is not there; that the vocational system has come? Of merely saying that a Conference of Education Secretaries took place, and that the States are adopting that system is not enough. The Central Government must come forward. How are we going to mould our young generation? How are students going to get jobs after finishing their graduation, under the new education system. Today job avenues are not much. My third point *is...(inter nipt ions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Let him answer your two points *first...(interruptions)*

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I would like to draw the attention to what the hon. Minister has said, Indian education system is to promote all aspects of material, mental, moral and spiritual. What is the meaning of introducing it in this, 1 want to know.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you start with the third point and then come to the first,

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Madam, this is a question which is related only to vacational education. For this question, 1 need separate notice. I will give the answer in great detail, as 1 am doing today. It does not relate to education policy; it does not relate to other aspects, it only relates to vocational education. So, I need your protection.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am sorry. Let me know some of these things. 1 would like to know about the vocational system; what is being done now? I would like to know about the vocational system; forget the policy. To what extent the Government has achieved; to what extent it has implemented?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Madam, this aspect I have answered earlier, that this scheme of vocational education was almost as good as dead. After the Eighth Plan, people realised that it was not working. So, the States took it over in the Ninth Plan, but they also did not implement it. It was only towards the end of Ninth Plan that we revised it. It is just the beginning of the first year of the Plan, The scheme is just on the road. We cannot have any result out of it immediately. It could take three-four years to evaluate the result of this scheme. So, it would be very difficult to say, how much we have been able to achieve in terms of employment, how many employable students will come out etc. We can say only when the students come out. this scheme has just started.

श्री रमा शंकर कौशिकः उपसभापति महोदया, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 910 स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि केन्द्र सरकार के प्रस्तावों और केन्द्र की सरकार की सहायता से वहां पर व्यासायिक शिक्षा शुरु की गई थी और कई वर्षों से वह चल रही है लेकिन वहां पर जो टीचर्स हैं जो एक लाख बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं, उनको महीने में 1500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। कई बार उन्होंने माननीय मंत्री जी को मानदेय बढ़ाने के बारे में लिखा है, मैंने भी माननीय मंत्री जी को इसके बारे में लिखा है।

उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन व्यासायिक शिक्षकों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाने के लिए कब तक वह फैसला कर लेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः महोदया, यह मानदेय सभी राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। हमारी तरफ से...

श्री रमा शंकर कौशिकः लेकिन यह आपसे भी संबंधित है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः हम तो उनका पैसा देते हैं। विभिन्न राज्यों में इसकी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। आपकी यह सद्इच्छा और आपका यह सुझाव मैं उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रेषित कर दूंगा कि आपने यह सुझाव दिया है कि इसको बढ़ाने की जरुरत है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेः माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पिछले दस वर्षों से देश के कई राज्यों में 10+2 परीक्षा प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अतिरिक्त एक डिवीजन रखी गयी है, पास डिवीजन और यह माना गया है कि उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने का अधिकार नहीं होगा और वे केवल वोकेशनल सैंटर्स में ही जाएंगे लेकिन वोकेशनल सैंटर्स पर्याप्त नहीं है। मंत्री जी ने जैसे यहां पर बताया कि 35 यूनिवर्सिटीज

और 1635 कालेज हैं। इसलिए मैं यह पूछना चाहूंगी कि इन 35 यूनिवर्सिटीज और 1635 कालेजिज के लिए कितनी मनी ऐलोकेट की गयी है? इसके अतिरिक्त यहां पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है? क्या महिलाओं के लिए किसी विशेष तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है जो खाना बनाने और सिलाई कढ़ाई के अतिरिक्त हो? इसके अलावा यू.जी.सी. में कैरियर ओरिएंटिड स्कीम, जिसका यहां जिक्र किया गया है, क्या उसके तहत अब तक कुछ स्टूडेंट्स बैनिफिटिड हुए हैं?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः आपके प्रश्न के दो भाग हैं। जहां तक इस बात का सवाल है, बहुत से विश्वविद्यालय जो राज्य सरकारों के हैं? राज्य सरकारें उन विश्वविद्यालयों के लिए पैसा देने की जिम्मेदारी रखती हैं। यू.जी.सी. जिस प्रकार से प्रोजैक्ट्स आते हैं, डेवलपमेंट प्रोजैक्ट्स आते हैं, उस हिसाब से उनको पैसा देती है। जहां कहीं इस नये क्षेत्र को खोलने के लिए पैसा मांगा गया होगा, उसमें उनको मूल्यांकन के पश्चात् पैसा दिया गया होगा लेकिन यह जिम्मेदारी मूलतः राज्यों में राज्य विश्वविद्यालयों की है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जहां कहीं ऐसा विधान होगा, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा किन्तु शायद ही किसी विश्वविद्यालय में ऐसा हो।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेः महिलाओं के लिए उनकी खास स्किल को देखते हुए क्या उन्हें ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः राज्य सरकारें अपने यहां प्रवेश ...(**व्यवधान**)... कि किस विश्वविद्यालय में जाएंगी, किस स्ट्रीम में जाएंगीं? आप इस संबंध में कोई सुझाव देंगी तो मैं राज्य सरकारों को भेज दूंगा।

उपसभापतिः वह कह रही हैं कि महिलाओं को सिर्फ खाना पकाने, रोटी पकाने, कपड़ा सीने पर ही रखेंगे या उनकी और कैपेसिटी बढाएंगे।

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः महिलाओं की दृष्टिं से अनेक व्यावसायिक शिक्षा योजनाएं हैं जैसे महिला पॉलीटैक्नीक्स हैं, महिला बायो टैक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं और महिलाओं से संबंधित इलैक्ट्रोनिक उद्योगों की टैक्नोलॉजी है। इसकी शिक्षा की व्यवस्था विभिन्न पॉलीटैक्नीक्स के अंदर की गयी है। बायो टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम विशेष रूप से महिलाओं के लिए केन्द्र खोल रहे हैं। इसी प्रकार महिला पॉलीटैक्नीक्स भी खोल रहे हैं जिसमें विभिन्न उद्योगों की और विभिन्न टैक्नोलॉजीज़ की शिक्षा उन्हें दी जा रही है। मैं ऐसा देख रहा हूं कि इन क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवेश काफी अधिक होता जा रहा है जो एक शुभ लक्षण है।

SHRI B.P. SINGHAL: Madam, more important than having the vocational institutions is the requirement of some requisite qualifications for each young man—that is, his physical, intellectual, moral, spiritual and aesthetical

sensitiveness towards that education. Now, unless those qualifications are prescribed, we cannot achieve the desired result. About ten years ago, I **saw** one book in Maharashtra in which they had given a list of vocations. That was a very good effort. But, more than that, the necessary qualifications have to be prescribed so that a child can select that particular vocation for himself and start cultivating those qualities that are needed for that education. 1 say this from my own experience. In the first year of my graduation, I decided to join the Indian Police Service, and I tell you, Madam, that nobody could stop me from achieving my goal, because, I had developed myself from my intermediate days upto the time 1 passed my Law. That is what is important. There is a complete absence of direction. ...*(Interruptions)*

उपसभापतिः आप मंत्री जी को बता दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो वह पूछ लीजिए।

SHRI B.P. SINGHAL: Madam, the qualification needed for each avocation must be made known far and wide so that children can prepare themselves for a particular job. Is the Government contemplating to issue any such literature in large scale in schools, at the high school level, so that children can attain those qualifications?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः महोदया, यह प्रश्न इससे संबंधित है कि जहां राज्य सरकारें अपने यहां विद्यालयों में इन कक्षाओं को खोल रही हैं, वहां इसके लिए आवश्यक योग्यता और आवश्यक पाठ्यक्रम क्या है, उसका प्रसारण वे करें। हम इस सुझाव को विभिन्न राज्य सरकारों के पास भेज देंगे कि अच्छा हो कि वे उन सभी विद्यालयों में विभिन्न प्रसारण माध्यमों से इस बात को बताएं कि इनमें प्रवेश लेने के लिए कौन-सी योग्यताएं और कौन से पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और बच्चों को किस प्रकार से उनको करना चाहिए। कोशिश यह भी की जा सकती है कि काउंसिलिंग की जाए और उसकी व्यवस्थाएं भी राज्य सरकारें कर सकती हैं, तो वे जरुर करें।

Dope Test-failed Indian weight-lifter at **Manchester**

*163.SHRI. B.J. PANDA:†
MISS MABEL REBELLO:

Will the Minister YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to **state:**

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report captioned, "Manchester drug disgrace-Government knew there was suspect in team", which appeared in the Indian Express dated the 3rd September, 2002;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri B. J. Panda.